नईदुनिया

बैरिकेडिंग तोड़ी, वाटर कैनन का इस्तेमाल, कई छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

पटना में छात्रों का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास मार्च के दौरान हँगामा

नईदुनिया ब्यूरो, पटनाः पेपर लीक और रोजगार की मांग को लेकर मंगलवार को पटना में छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने इनकम टैक्स गोलंबर और जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग की, लेकिन छात्रों ने आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे रहे और नारेबाजी जारी रखी। कुछ छात्र सड़क पर बैठ गए, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी वाटर कैनन के बीच प्रदर्शन करते रहे। बाद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हटाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया। प्रदर्शन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम तथा अन्य नेताओं ने भी छात्रों का समर्थन किया। पुलिस ने विनोद जाखड़, राजेश राम और छात्रा भाग्य भारती को हिरासत में लिया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी प्रदर्शन में शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें रखीं। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि वे पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप था कि उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस आंदोलन को युवा कांग्रेस, एआईएसएफ, छात्र राजद, एसएफआई, डीवाईएफआई, द ग्रेट भीम आर्मी, सोशल जस्टिस आर्मी, एआईडीएसओ, द सोशलिस्ट और एआईडीवाईओ सहित कई छात्र एवं सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ। पुलिस ने फिलहाल प्रदर्शनकारियों को मुख्य मार्गों से हटाकर स्थिति सामान्य कर दी है।

विदेश मंत्री अराघची को हटाने महाभियोग की तैयारी, राष्ट्रपति की भूमिका सीमित होने की चर्चा

अमेरिका व इजराइल से युद्ध के बीच ईरान में राजनीतिक संघर्ष

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः ईरान में विदेश मंत्री अब्बास अराघची के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की खबरों ने देश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कुछ सांसद उनके खिलाफ आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य जुटा रहे हैं। वरिष्ठ सांसद होसैनअली हाजीदेलिगानी ने कहा है कि उचित समय आने पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि राष्ट्रपति मसूद पजशकियान की भूमिका विदेश और सुरक्षा नीति के मामलों में सीमित होती जा रही है। बताया जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका के साथ संभावित वार्ता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के

कमांडर अहमद वाहिदी की भूमिका अधिक प्रभावशाली मानी जा रही है। हालांकि, इन दावों पर ईरानी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित वार्ता की तारीख और स्थान अब तक तय नहीं हो सके हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान और कतर संभावित मेजबान देशों के रूप में चर्चा में हैं तथा दोनों देश मध्यस्थता के प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान अब प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के बजाय समुद्री व्यापार, तेल आपूर्ति और महत्वपूर्ण नौवहन मार्गों पर दबाव बनाकर अपने रणनीतिक हित साधने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर, आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर उड़ रहे एक एमक्यू-9 रीपर ड्रोन को वायु रक्षा प्रणाली से मार गिराया। हालांकि, ड्रोन किस देश का था, इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

उधर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरान पर दबाव बढ़ाने के नए विकल्पों पर अपने सैन्य विश्लेषकों से सुझाव मांगे हैं। वहीं, यमन के हूती विद्रोहियों की धमकियों के बाद छह सऊदी सुपरटैंकरों ने लाल सागर और बाब-अल-मंदेब मार्ग के बजाय अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से से लंबा समुद्री मार्ग अपनाया है। इससे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं।

देशभर में बरसात का कहर जारी बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत

- बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन से 200 यात्री फँसे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलभराव से जनजीवन प्रभावित

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बिहार और पश्चिम बंगाल में सोमवार को बिजली गिरने से कुल 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए।

मृतकों में बिहार के विभिन्न जिलों के सात और पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के चार लोग शामिल हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो गया।

पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर सड़क पर आने के कारण मार्ग बंद हो गया, जिससे लगभग 200 यात्री सोमवार रात से रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से मार्ग को बहाल करने के प्रयास जारी हैं। हरियाणा के अंबाला और झज्जर में रातभर हुई तेज बारिश के कारण कई सड़कों पर जलभराव हो गया। अनेक स्थानों पर सड़कें तालाब जैसी दिखाई दीं और कई दुकानों में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के आगरा में देर रात से रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में दो से तीन फीट तक पानी भर गया।

जलभराव को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। वहीं, बाराबंकी में लगभग दो घंटे की तेज बारिश से बस स्टेशन परिसर में पानी भर गया, जिससे यात्रियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विभिन्न राज्यों में प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है।

दक्षिण कोरिया में भीषण गर्मी का कहर, तापमान ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड

सियोल, एजेंसीः दक्षिण कोरिया इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश के गृह मंत्रालय के अनुसार, अत्यधिक गर्मी के कारण अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 मई से 2 अगस्त के बीच 2,025 लोग गर्मी से संबंधित बीमारियों से प्रभावित हुए हैं। रविवार को यांगसान शहर में 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो दक्षिण कोरिया के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक तापमान है। इससे पहले देश में सबसे अधिक तापमान एक अगस्त 2018 को 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौजूदा वर्ष में यह रिकॉर्ड लगातार तीन बार टूटा है। 31 जुलाई को तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस, दो अगस्त को 41.6 डिग्री सेल्सियस और तीन अगस्त को 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

लगातार बढ़ते तापमान के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव बढ़ा है। बड़ी संख्या में लोगों को लू और गर्मी से जुड़ी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उपचार की आवश्यकता पड़ी है। प्रशासन ने नागरिकों से अत्यधिक गर्मी के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने तथा स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की अपील की है। लगातार बढ़ते तापमान और बार-बार टूट रहे रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया में इस वर्ष असामान्य गर्मी की स्थिति को दर्शाते हैं।

डाबर के '100% शुद्ध' दावों वाले उत्पादों की बिक्री पर लगी रोक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने डाबर के कई खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कार्रवाई उन उत्पादों पर की गई है, जिनका प्रचार '100 प्रतिशत शुद्ध', '100 प्रतिशत नेचुरल', '100 प्रतिशत प्योरिटी गारंटीड', '100 प्रतिशत ऑर्गेनिक' और '100 प्रतिशत टेंडर कोकोनट वॉटर' जैसे दावों के साथ किया जा रहा था। इनमें शहद, गाय का घी तथा अन्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं। कंपनी से 15 दिनों में रिपोर्ट भी मांगी है। कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित कई दावे भ्रामक पाए गए हैं। प्राधिकरण का कहना है कि '100 प्रतिशत' जैसे दावों का उपयोग खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि ऐसे दावे उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले माने जाते हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा- निजी कार्यक्रम से सरकार का कोई संबंध नहीं

हसीना के संबोधन से भारत ने बनाई दूरी, बांग्लादेश ने जताई थी आपत्ति

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रस्तावित ऑनलाइन संबोधन से उसका कोई संबंध नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है और भारत सरकार न तो इसका आयोजन कर रही है और न ही मंच पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों का समर्थन करती है।

शेख हसीना पांच अगस्त को वीडियो लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ने

के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक संबोधन होगा। कार्यक्रम में उनके पुत्र सजीब वाजेद जॉय और अवामी लीग के अन्य नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है।

इससे पहले बांग्लादेश ने भारत से अनुरोध किया था कि शेख हसीना या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को भारतीय भूमि से राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने अथवा भाषण देने की अनुमति नहीं दी जाए। ढाका का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से दोनों देशों के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यह मुद्दा हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर और ढाका में भारत के उच्चायुक्त के बीच हुई बैठक में भी उठाया गया था।

पांच अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद छोड़कर बांग्लादेश से भारत का रुख किया था। उसी तारीख को दो वर्ष बाद उनके सार्वजनिक संबोधन को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रियांक खड़गे के बयान पर सियासी विवाद, भाजपा ने मांगा इस्तीफा

- भर्ती परीक्षा विवाद पर टिप्पणी के बाद बढ़ा राजनीतिक टकराव, मंत्री ने कहा- बयान को गलत ढंग से पेश किया गया

नईदुनिया ब्यूरो, बेंगलुरुः कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के एक बयान को लेकर राज्य की राजनीति में विवाद गहरा गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग उनका इस्तीफा चाहते हैं, वे पहले 25 दिन भूख हड़ताल करें और फिर लाठीचार्ज का सामना करें। बाद में प्रियांक खड़गे ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। विवाद विजयपुरा में आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान सामने आया, जहां कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि ओएमआर शीट के क्रमांक प्रश्न पत्र से मेल नहीं खा रहे थे। इसके बाद कई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से बाहर आ गए और दोबारा परीक्षा कराने की मांग करने लगे। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र के क्रमांक का समान होना आवश्यक नहीं है। प्राधिकरण के अनुसार, केवल प्रश्न पत्र की सीरीज और वर्जन कोड का सही उल्लेख अनिवार्य होता है।

साइबर फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरबीआई को एसओपी बनाने के निर्देश

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को साइबर फ्रॉड से जुड़े बैंक खातों और म्यूल अकाउंट्स से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर सभी संबंधित संस्थाओं के बीच प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक समान प्रक्रिया आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। पीठ ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पुलिस विभागों को भी निर्देश दिया कि साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए विकसित शिकायत निवारण और धनवापसी प्रणाली को शीघ्र लागू किया जाए, ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके।

विरोध *अधिक स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकारों को लेकर प्रदर्शन जारी, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता बेनतीजा...*

पाक अधिकृत कश्मीर में 12 आरक्षित सीटें खत्म करने की मांग

मुजफ्फराबाद, एजेंसीः पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में महंगाई के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन अब राजनीतिक अधिकारों और अधिक स्वायत्तता की मांग तक पहुंच गया है। आंदोलन का नेतृत्व जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) कर रही है, जिसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर विधानसभा की 45 सीटों में से 12 आरक्षित सीटों को समाप्त करने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि ये सीटें पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं और इनके कारण स्थानीय मतदाताओं की भूमिका कमजोर होती है। जेएएसी का

गठन वर्ष 2023 में व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने किया था। शुरुआत में संगठन ने महंगी बिजली और आटे की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन किया था। वर्ष 2024 और 2025 के प्रदर्शनों के बाद सरकार ने बिजली दरों में कमी और आटे पर सब्सिडी देने जैसे कदम उठाए थे। इसके बाद संगठन का जनाधार बढ़ा और उसने राजनीतिक सुधारों की मांग भी शुरू कर दी। संगठन ने रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था, लेकिन उससे पहले सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जेएएसी पर प्रतिबंध लगा दिया और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन जारी रहे। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार जून की शुरुआत से 27 जुलाई तक प्रदर्शनकारियों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों सहित कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है।

कठुआ में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी

नईदुनिया ब्यूरो, जम्मूः जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में मंगलवार को पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई देने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, दोपहर करीब दो बजे एक ड्रोन भारतीय सीमा में प्रवेश कर हीरानगर सेक्टर के बोबियान क्षेत्र स्थित शुखमल, देविंदरा और तपन गांवों के ऊपर कुछ समय तक मंडराता रहा। ड्रोन की गतिविधि का पता चलते ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उसे मार गिराने के लिए जवाबी कार्रवाई की। हालांकि, ड्रोन अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसके कारण वह भारतीय क्षेत्र से वापस पाकिस्तान की ओर लौट गया। घटना के बाद सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने पूरे इलाके में संयुक्त रूप से सघन तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन की घुसपैठ के उद्देश्य और संभावित गतिविधियों की जांच कर रही हैं। सीमा से सटे गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।